

मुख्यमंत्री की आलोचना करने से बचें राणा दम्पति

अन्यथा शिवसेना स्टाइल में दिया जाएगा जवाब, राजकमल चौक पर किया प्रदर्शन



प्रतिनिधि, 20 अक्टूबर अमरावती- विगत दिनों जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री उध्व ठाकरे पर कोरोना काल के दौरान घर में बैठे रहने का आरोप लगाते हुए आह्वान किया था कि, उन्होंने घर से बाहर निकलकर राज्य का दौरा करना चाहिए, साथ ही राणा दम्पति ने सीएम ठाकरे की कामकाज को लेकर आलोचना भी की थी। जिससे संतप्त होकर शिवसेना की महानगर शाखा ने मंगलवार, 20 अक्टूबर को स्थानीय राजकमल चौक पर तीव्र आंदोलन करते हुए राणा दम्पति का निषेध किया और उनके छायाचित्रवाले पोस्टर पर चप्पल-जूते बरसाये और राणा दम्पति को चेतावनी दी कि वे केवल जिले और अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विकास कामों पर ध्यान दें तथा



सीएम उध्व ठाकरे के खिलाफ नाहक आरोप-प्रत्यारोप न करें। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुड्डे के नेतृत्व में किये गये आंदोलन में कहा गया कि, मेलघाट का पिकनिक दौरा करनेवाले सांसद नवनीत व विधायक रवि राणा एक तरफ तो राज्य के मुख्यमंत्री पर बेसिरपैर के आरोप लगा रहे हैं, वहीं खुद उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित काविड सेंटर में एक महिला को छेड़खानी का सामना करना पड़ा है। इसी तरह मेलघाट के धारणी गांव में विगत शुक्रवार को एक युवती को खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया गया। किंतु सांसद व विधायक राणा दम्पति ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे में राणा दम्पति को चाहिए कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें और बिना मतलब अन्य मामलों में पैर न फंसाये। इस आंदोलन के दौरान शिवसेना पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सांसद व विधायक के खिलाफ जबर्दस्त नारेबाजी करने के साथ ही उनके छायाचित्रवाले पोस्टरों पर चप्पल व जूते बरसाये। इस आंदोलन में पूर्व सांसद अनंत गुड्डे, शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े, सहसंपर्क प्रमुख ज्ञानेश्वर धाने पाटिल व प्रशांत वानखड़े, महिला

ट्रांसपोर्ट सेल को नो एंट्री में राहत देने की मांग

भाजपा के जिला संयोजक पावड़े ने प्रशासन को सौंपा पत्र

प्रतिनिधि, 20 अक्टूबर अमरावती - शहर पुलिस आयुक्त द्वारा 7 अक्टूबर से शहर में नो एंट्री के नियम में बदलाव कर अधिसूचना जारी की गयी है। पर इस अधिसूचना में बड़े वाहनों को शहर में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गयी है। ऐसे में अमरावती जिले का संपूर्ण व्यापार व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय रुकने के लिए शहर की नागरिकों को कोई भी परेशानी ना हो इसके चिंता सभी को है। ऐसे में नो एंट्री की लगायी गयी शिथिलता पर राहत देने की मांग भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट सेल के जिला संयोजक सुधीर पावड़े ने जारी किए गए प्रसिद्धि पत्रक में की है। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट द्वारा संपूर्ण शहर व शहर के बाहर से आनेवाला जीवनावश्यक माल की आपूर्ति होती है। अमरावती शहर में 25 से 30 ट्रक भारत के विभिन्न राज्यों से आवश्यक सामग्री लेकर पहुंचते हैं। जिनमें कृषि साहित्य, अनाज, दवाइयां, खाद्य पदार्थ, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टाइल्स, एमआयडीसी उद्योग के लिए लगनेवाला माल करीब एक ट्रक में 500 से 600 बॉक्स लाए जाते हैं। उस माल को खाली कर ऑटो व रिक्शा के जरिए संबंधित संचालक को पहुंचाया जाता है। ऐसे में अधिसूचना के लिए दिया गया समय यह पूर्ण नहीं है। जिसके चलते ट्रक चालक से लेकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों में नाराजगी फैल चुकी है। इसलिए पूर्वता की तरह शिथिलता को राहत देकर नो एंट्री में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को ट्रक आवाजाही को अनुमति दिए जाने की मांग भाजपा ट्रांसपोर्ट द्वारा की गयी है।

वाहन चालकों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण

प्रतिनिधि, 20 अक्टूबर अमरावती- कोरोना महामारी का प्रकोप टालने के लिए मास्क का उपयोग करना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महामार्ग नंबर-6 पर शनिवार को मारवाड़ी युवा मंच और महामार्ग पुलिस के सहयोग से वाहन चालकों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। यहां बता दें कि चहुंओर कोरोना महामारी ने कहर बरपाने का काम किया है। बाहरी राज्यों से लंबी दूरियों से माल की ढुलाई करने वाले वाहन चालकों पर कोरोना का प्रकोप ना हो इसके लिए वाहन चालकों को मास्क का वितरण किया गया। इसके अलावा सैनिटाइजर का वितरण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के संबंध में जनजागृति की गई। इस अवसर पर नागपुर अकोला महामार्ग क्रमांक-6 पर स्थित महामार्ग पुलिस मदद केन्द्र नागझिरा बडनेरा के प्रभारी अधिकारी सुगत पुंडगे, पुलिस कर्मचारी वासुकर, अनिल, सुधीर राजत, मंगेश रौराले, सचिन मोहकर, अंकुश पायधन, युवा मंच के संकेत गोयनका, अमित मंत्री, भूपण हरकुट, मोहित सारडा, प्रदीप अग्रवाल, पीयूष गोयनका आदि उपस्थित थे।

नौकरी पाने की लड़ाई ने फिर परिवार के साथ अनशन पर बैठने किया मजबूर

प्रतिनिधि, 20 अक्टूबर अमरावती- बुलढाणा जिले के स्व. दुर्गा बनेरुकर विज्ञान महाविद्यालय लोणार में पूरा समय सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त प्रा. डॉ. प्रवीण गायकवाड़ को अचानक पूर्व सूचना न देते हुए काम से कम किया गया। उनके साथ अन्य और कर्मचारियों को काम से कम किया गया। न्यायिक लड़ाई के बाद उन्हें महाविद्यालय में पूर्ववत करने के आदेश होने के बाद भी अब तक उन्हें पूर्व पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण फिर एक बार बीड़ जिला निवासी प्रा. डॉ. प्रवीण गायकवाड़ पर अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठने की नौबत आई है। बता दें कि साल 2016 में प्रा. डॉ. प्रवीण गायकवाड़ को लोणार के महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद पर पूरे समय के लिए नियुक्त किया गया था। एक साल बाद महाविद्यालय ने पूर्व सूचना न देते हुए उनके साथ पदभर्ती किये सभी लाभभंग सभी को काम से कम किया। जिसकी उन्होंने शिक्षा सहसंचालक डॉ. अर्चना नेरकर



से शिकायत की थी। साल 2018 में उन्होंने प्रा. डॉ. प्रवीण गायकवाड़ व उनके साथियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। जिसके पश्चात यह मामला विविध विभागों से होते हुए उच्च स्तर तक पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कई बार आंदोलन किये। परिवार के साथ अनशन लगा आंदोलन किया, जिसकी दखल लेते हुए उन्हें सुनवाई के लिए आमंत्रित किया गया। नियुक्ति मामले में प्रशासक की नियुक्ति की गई है। प्रशासन ने 10 दिनों बाद मामले की रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन दिया था, किंतु अब प्रशासन प्रा. डॉ. प्रवीण गायकवाड़ व उनके सहकारी प्रा. अवीरेशी देहे को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस काल में प्रशासन को परेशान करने की हमारी मन्शा नहीं है। लेकिन प्रशासन द्वारा इस मामले का तत्काल न्याय करें तथा महाविद्यालय में पूर्व पद पर नियुक्ति दी जाए, यह मांग करते हुए प्रा. डॉ. प्रवीण गायकवाड़, मां चंद्रकला, पत्नी विद्या, बेटी प्रांजल,

बीड़ निवासी प्रा. डॉ. प्रवीण गायकवाड़ की कहानी

संभागीय सहसंचालक कार्यालय के सामने आंदोलन

मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल का पुनर्गठन कर कर्ज वितरित करें

बडनेरा वेलफेयर सोसायटी की मंत्री नवाब मलिक से गुहार



प्रतिनिधि, 20 अक्टूबर अमरावती- केन्द्र सरकार ने साल 2013 में मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल योजना बंद की। इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, किंतु विगत 7 वर्षों से युवा सरकारी अनुदान से वंचित हैं। वे अपना रोजगार शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल का पुनर्गठन करने की मांग बडनेरा वेलफेयर सोसायटी ने की। मंगलवार को जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश के माध्यम से केन्द्रीय अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक को पत्र भेजा गया। जिसमें बडनेरा वेलफेयर सोसायटी ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में कई युवाओं के रोजगार छिन चुके हैं। वे अपना स्वयंरोजगार शुरू करना चाहते हैं, किंतु युवा वर्ग के पास आर्थिक अनुदान न रहने से वे रोजगार शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आर्थिक सहायता मिले इस उद्देश्य से बंद पड़े मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल को शुरू किया जाए, यह मांग सोसायटी ने की। पत्र सौंपते समय सोसायटी के अध्यक्ष जाकीर जमाल, जावेद खान, मोहम्मद रिजवान, जफर खान, मो. जाकीर, मोहम्मद जफर, अजमत खान, शब्बीर भाई, अब्दुल रजीक, अ. अलीम, इमिनयाज अहमद, वसीम पटेल, मोहम्मद इमरान, इशारा खान, अताउल्ला खान, मोहम्मद शोएब, मो. शहजाद, वसीम मो खान, अब्दुल मलिक, फह्रान अंसारी, शब्बीर पत्रकार, बबलू खान, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद मुदरिस, मोहम्मद

ईएसबी शॉपिंग फेस्टिवल : आकर्षक उपहारों की बौछार

शॉपिंग फेस्टिवल में डिस्काउंट, ऑफर, फ्री गिफ्ट, लकी ड्रा, त्योहारों के महेनजर फेस्टिवल ऑफर को ग्राहकों का शानदार प्रतिसाद



प्रतिनिधि, 20 अक्टूबर अमरावती- ब्रांडेड वस्तुओं से ग्राहकों के दिलो पर राज करने वाले ईएसबी का शॉपिंग फेस्टिवल ग्राहकों की सेवा में फिर एक बार दस्तक दे चुका है। आगामी दशहरा व दीपावली के त्योहार के महेनजर ईएसबी के शॉपिंग फेस्टिवल में ग्राहकों को शॉपिंग का आनंद लेते हुए डिस्काउंट, ऑफर, फ्री गिफ्ट के साथ लकी ड्रा द्वारा आकर्षक उपहारों की बौछार होगी। यह फेस्टिवल ग्राहकों की सेवा में शुरू हो चुका है, जिसका ग्राहक भी बड़े-चढ़कर लाभ ले रहे हैं। स्थानीय रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित ईएसबी मॉल में ग्राहकों के लिए एक छत के नीचे कपड़ों से लेकर घर सजावट का हर सामान यहां उपलब्ध है। देश की नामचीन कंपनियों के ब्रांड ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध है। ग्राहकों तक केवल बेहतरीन ब्रांड पहुंचाना यही ईएसबी की खासियत ही नहीं बल्कि उन्हें कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऑफर के लाभ देने का प्रयास भी ईएसबी करता है। अन्य मॉल के मुकाबले ईएसबी की अलग पहचान बन चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी ईएसबी मॉल अपने ग्राहकों के लिए आगामी त्योहारों के महेनजर बेहतरीन ऑफर लेकर आया है।

ग्राहकों की सेवा ही हमारा लक्ष्य

ईएसबी की संचालिका स्वस्तिका योग भूत ने कहा क ग्राहकों की सेवा में ईएसबी हमेशा ही तत्पर रहा है। बदलते फैशन के साथ हमें अपना लुक बदलने का मौका मिले यह कोशिश ईएसबी करता है। जिसमें कुछ हद तक हम कामयाब हुए हैं। आने वाली तीज त्योहारों के महेनजर रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित ईएसबी में जो डिस्काउंट, ऑफर, फ्री गिफ्ट के साथ लकी ड्रा आयोजन किया है। उसका ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लाभ लें, यह अनुरोध उन्होंने किया। जिसमें लक्झरी बेडशीट, लक्झरी क्रॉचरी सेट, डफ्ल बैग, जीम बैग का समावेश है। वहीं लकी ड्रा विजेताओं को एलडीडी टीवी, वाशिंग मशीन, मायक्रोवेव सेट दिया जाएगा।

चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल पर मनपा सुस्त

राजकमल, गर्ल्स हायस्कूल के अलावा सभी सिग्नल ठप, सैकड़ों दिक्कतों के बावजूद यातायात विभाग मुस्तैद



प्रतिनिधि, 20 अक्टूबर अमरावती - शहर की उलझी यातायात को लेकर कई बार सड़कों पर मेगा ब्लॉक की तस्वीर नजर

इन सिग्नलों की बत्ती गुल

सिग्नल लगाने के पश्चात उसका मेन्टेन्स और उपयोग समय-समय पर किया जाना जरूरी है। परंतु मनपा प्रशासन द्वारा पल्ला झाड़ने से यह समस्या बढ़ती जा रही है। शहर के कुछ मार्गों पर सड़क निर्माण कार्य शुरू रहने के चलते दीपक चौक, मालवीय चौक का सिग्नल बंद है। तो टेक्निकल दिक्कतों के चलते गोपाल नगर, दस्तूर नगर, रुमिणी नगर, पंचवटी चौक, शेगांव नाका, बियाणी चौक, कठोरा नाका, इर्विन चौक सहित कई सिग्नलों की बत्ती पिछले कई माह से गुल है। आती रही है। तो हर चौराहे पर दुर्घटना जैसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिसे लेकर हमेशा यातायात विभाग पर ही निशाना साधा जाता है। परंतु शहर के चौराहे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल को लेकर मनपा पूरी तरह से सुस्त नजर आ रही है। जिसका खामियाजा यातायात विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को इन दिनों भुगतना पड़ रहा है। शहर के दर्जनों से ज्यादा सिग्नल ठप रहने से यातायात पुलिस पर दबाव बढ़ा है। शहर में केवल राजकमल चौक व गर्ल्स हाईस्कूल चौराहे पर ही सिग्नल शुरु दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि शहर में यातायात को नियंत्रित रखने हेतु पूर्व-पश्चिम के दो विभागों में बंटा गया है। दोनों ही विभागों में हमेशा सड़कों पर भीड़ लगी रहती है। चौराहे पर सिग्नल रहने से

यहां पर नए सिग्नलों का प्रावधान

हाल ही में पुलिस आयुक्त डा. आरती सिंह द्वारा यातायात विभाग की बैठक लेकर दिशा-निर्देश दिये गए थे। बंद पड़े सिग्नलों के साथ-साथ आवश्यक जगहों पर सिग्नल लगाने की बात कही गई थी। जानकारी के मुताबिक आगामी दिनों में चिन्ना चौक, टांगा पड़ाव तथा गांधी चौक पर नए सिग्नल लगाए जाएंगे। दुर्घटनाओं को बड़े पैमाने पर रोका जा सकता है। तो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा सकती है। यातायात के नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के साथ कई तरह की राहत निश्चित है। परंतु प्रशासन ही नियोजन में सुस्त रहने से नागरिक भी नियमों की धजियां उड़ाते फिरते हैं। उसके बावजूद शहर की अस्तव्यस्त यातायात से लेकर बंदोबस्त में तैनात रह कर यातायात विभाग के कर्मचारी ड्यूटी को लेकर मुस्तैद हैं। बीते दो वर्षों में कई तरह के हाईटेक्निक का उपयोग यातायात विभाग द्वारा किया जा रहा है। परंतु चौराहों के सिग्नल बंद रहने से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं तो अवैध पार्किंग से लेकर सड़कों पर लंबा जाम दिनों-दिन बढ़ रहा है। जब तक शहर के निर्धारित सभी सिग्नल शुरु नहीं होते तब तक मेगाब्लॉक की यह परेशानी बरकरार रहेगी।

किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपए नुकसान भरपाई दें



राष्ट्रीय समाज पक्ष के जिलाध्यक्ष प्रदीप पातुर्डे की जिलाधीश से मांग

अमरावती- जिले में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इन फसलों को हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार ने हर किसान को प्रति एकड़ 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से शासन तक पहुंचाना चाहिए। शासन द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता घोषित नहीं की गई तो चक्काभंग आंदोलन कर सरकार का

निषेध व्यक्त किया जाएगा, यह चेतावनी राष्ट्रीय समाज पक्ष की ओर से प्रदीप पातुर्डे ने की। मंगलवार को जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचकर उन्होंने अतुल इंग्ले, इंद्र लक्वले, पवन बड़े, अश्व कोत्रे, रोशन कोत्रे, प्रमोद पातुर्डे, विजय कोत्रे, रामानंद लक्वले, रविंद्र भागवत आदि उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने कहा कि किसान हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य में गैला अकाल घोषित करना चाहिए। साथ ही किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए उन्हें प्रति एकड़ 50 हजार रुपए की सहायता प्रदान करनी चाहिए। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सहायता से किसानों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। साथ ही उन्हें आने वाली रबी की बुआई के लिए सरकारी अनुदान राशि का लाभ मिलेगा।